

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क० 1097 एक/2007 विरुद्ध आदेश अंतरिम आदेश तथा अंतिम आदेश दिनांक 12-04-07 पारित अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी प्रकरण क्रमांक 16/अपील/06-07.

- 1- महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. सुभाषचन्द्र
- 2 दिलीप सिंहल पुत्र स्व. सुभाष सिंहल
- 3 मनीषा पत्नी स्व. सुभाष चन्द्र
- 4 अनिलकुमार पुत्र स्व. बालकिशनदास
द्वारा मुख्तयारआम कैलाश सिंहल पुत्र
स्व. बालकिशन दास सिंहल
समस्त नि० निजी नवग्रह मंदिर के पीछे,
कमलागंज, शिवपुरी, म०प्र०

----- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- महिला भगवती देवी पत्नी स्व. जंगबहादुर अष्ठाना
- 2 अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी
श्री आदित्य सिंह तोमर

----- अनावेदकगण

श्री कैलाश सिंहल, मुख्तयारआम - आवेदकगण
श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक- अनावेदक क०- 1
श्री एच०के० अग्रवाल, पैनल अभिभाषक- अनावेदक क० 2

आदेश

(आज दिनांक 25.6.2014 को पारित)

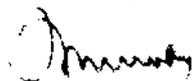
यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/06 07 में पारित अंतरिम



एवं अंतिम आदेश दिनांक 12-04-07 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

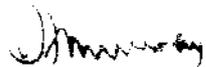
2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक भगवती देवी एवं हरीमोहन द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 23-11-02 एवं 09-10-06 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण द्वारा कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12-04-07 द्वारा आवेदकगण के कॉस आब्जेक्शन निरस्त किये हैं और इसी दिनांक 12-04-07 को अंतिम आदेश पारित कर भगवतीदेवी की अपील रवीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इन आदेशों के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण ने लिखित तर्कों में यह कहा है कि आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि सर्वे क. 215 के रकबा 205.33 वर्गमीटर क्षेत्र पर अनावेदकों ने बलपूर्वक कब्जा कर निर्माण कर लिया जो दिनांक 14-01-01 को हुए सीमांकन से प्रमाणित हुआ। अनावेदकों ने कब्जा रिक्त नहीं करने पर आवेदकों ने धारा 250 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 23-11-02 को अनावेदकों को विरुद्ध 7 दिवस में कब्जा रिक्त करने के आदेश हुए। अनावेदकों की अपील अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने दिनांक 26-02-03 को निरस्त कर दी और दिनांक 20-6-03, 26-5-04 एवं 12-9-05 को अनावेदकों के विरुद्ध सिविल जेल वारंट बनाने के आदेश तहसीलदार ने दिये। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने भी आवेदकों को कब्जा दिलाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार ने कई बार पटवारी एवं गिरदावर को मौके पर कब्जा दिलाने भेजा परन्तु कब्जा नहीं मिला। आवेदकगण का तर्क है कि अनावेदकों



की अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। इसलिये रैज्यूडिकेटा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील ग्राह्य करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। उनका यह भी तर्क है कि अंतरिम एवं अंतिम आदेशों के विरुद्ध एक ही अपील ग्राह्य करना संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 250 में अपील का प्रावधान न होकर केवल निगरानी का प्रावधान है जिसका क्षेत्राधिकार कलेक्टर को है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। आवेदकगण को अपील में कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकार है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण द्वारा कास आब्जेक्शन में उठाये गये मुद्दों पर निष्कर्ष निकाले बिना अनावेदक की अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय के धारा 250 के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क्र०-1 के अभिभाषक ~~श्री अभिभाषक~~ का तर्क है कि अनावेदक महिला भगवतीदेवी द्वारा मान. उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी और मान. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिये निर्देशानुसार ही अनावेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील ग्राह्य कर उसका निराकरण गुण-दोष पर करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का मकान भू-राजस्व संहिता प्रभावशील होने के पूर्व से बना है जिसमें वह निवासरस है। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत भूमि से 6 माह के अन्दर बेदखल करने पर ही कब्जा वापिसी हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का मकान बहुत पूर्व से बना होने से उसे संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत हटाने का आदेश देना अधिकारिता रहित है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।



5/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेखानुसार किया जाय।

6/ मैने मान. उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन क्रमांक 5595/2006 में पारित आदेश दिनांक 06-11-2006 का अवलोकन किया। मान. उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है-

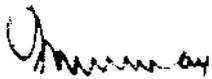
"Petitioners by Shri T.C.Singhal, Addocate.

This petition is filed by the petitioner challenging order dated 9/10/2006 passed by Tehsildar under Section 250 of M.P.Land Revenue Code.

The counsel for the petitioner prays for withdrawal of the petition with a liberty to filed appeal against the said order. In case if appeal is filed by the petitioner within 15 days from today, same shall be treated within limitation.

Petition stands disposed of with the aforesaid liberty."

मान. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि पिटीशनर द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-10-06 के विरुद्ध रिट पिटीशन प्रस्तुत की गयी थी और पिटीशनर द्वारा यह पिटीशन विथडा करने के निवेदन पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा अपील आदेश के दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने पर समयावधि में मान्य करने के आदेश दिये हैं। मान. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन में तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-10-06 को चैलेन्ज किया गया था और इसी आदेश के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने पर उसे मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समयावधि में होना मान्य किया जा सकता था। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील तहसीलदार के आदेश

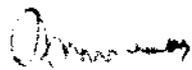


दिनांक 23-11-02 तथा पारिणामिक आदेश दिनांक 9-10-06 के विरुद्ध दिनांक 14-11-06 को प्रस्तुत की गयी है। मान. उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-10-06 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया अपील आवेदनपत्र सिर्फ समयवधि में होना मान्य किया जा सकता है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-10-06 अपील योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी को उभय पक्ष के तर्कों उपरान्त करना चाहिये था। तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-10-06 अंतरिम स्वरूप का है, इस कारण संहिता की धारा 46 (घ) के अनुसार तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-10-06 के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील ग्राह्य योग्य नहीं है। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-11-02 के विरुद्ध लगभग 4 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को माफ करने हेतु समयवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र शपथपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। म0प्र0 राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघ मर्या0 भोपाल तथा अन्य वि. पी0एस0कोटालकर (2010 राजस्व निर्णय 254) में राज्य सहकारी अधिकरण ने मान. उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 2004 रा.नि. 196 का अनुशरण करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि -

“समय वर्जित विवाद परिसीमा का प्रश्न का विनिश्चयन किए बिना आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती- न्यायालय का यह आबद्धकर कर्तव्य है कि पहले-हपल परिसीमा के प्रश्न का विनिश्चय करें।”

रामभुवन वि. रामविशाल (2002 रा.नि. 254) में राजस्व मण्डल द्वारा यही व्यवस्था दी गयी है कि

“समय वर्जित अपील- परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से विनिश्चित किया जाना चाहिये।”

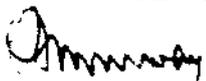


पी०के०रामचन्द्रन वि० स्टेट आफ केरला (1998 ए आई आर एससी: 2276) में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि satisfactory explanation के बिना विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। मंदिर श्रीराम जानकी वि. रामकुंवर बाई (2013 तीन: एम पी डब्ल्यू एन नोट नं. 69) में भी मान० उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि -

“ परिसीमा अधिनियम, 1963 -धारा 5- अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी- विलम्ब 2687 दिन का- उचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं- विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।”

उक्त न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक द्वारा विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं देने तथा विलम्ब माफी का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 23-11-02 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होने से ग्राह्य योग्य नहीं थी, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है।

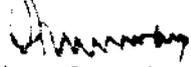
7/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियाँ से स्पष्ट है कि अनावेदक भगवतीदेवी आदि ने तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 15/ 2000-01/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 23-11-02 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो अनुविभागीय अधिकारी ने प्र.क्र. 38/2002-03/अपीलमाल पर पंजीबद्ध की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक भगवतीदेवी की यह अपील दिनांक 25-02-03 को अदम पैरवी में खारिज की गयी है। ऐसी दशा में पूर्व में अनावेदक भगवतीदेवी आदि द्वारा तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 15/ 2000-01/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 23-11-02 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी थी, इस कारण उनके द्वारा पुनः तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 15/ 2000-01/अ 70 में आदेश दिनांक 23-11-02 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2006 में



प्रस्तुत अपील रेसजूडिकेटा के सिध्दान्त के अनुसार सुनवायी योग्य नहीं थी। यदि अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के अदम पैरवी आदेश से असन्तुष्ट थी तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण को पुनःनम्बर पर लेने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करना चाहिये था या सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती देना चाहिये थी।

8/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख एवं आदेशों से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12-04-07 द्वारा आवेदकगण के कॉस आब्जेक्शन विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल होने से खारिज कर यह उल्लेख किया है कि 'रिस्पो. अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश के किसी सारवान विवादक का अवधारण मूल अपील के सुनवाई में बहस के दौरान करा सकता है। प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया जाता है, किन्तु इस अंतरिम आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 12-04-07 को ही अंतिम आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 12-04-07 तथा अंतिम आदेश दिनांक 12-04-07 निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-11-02 यथावत रखा जाता है।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0